

दुष्कालग्रस्त मराठवाड़ा को पानीदार कैसे बनाया जाए?

बीड ज़िले के १७ सिंचाई प्रकल्प रद्द, २६५४ कोल्हापुरी बांध बिना गेट के; डॉ. गणेश ढवळे ने की अजित पवार से ५२ करोड़ के प्रावधान की मांग



बीड, २१ जून: संवाददाता दुष्कालग्रस्त बीड ज़िले को पानीदार बनाने हेतु जलसंपदा विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए १७ सिंचाई प्रकल्पों को तीन वर्षों तक कार्य शुरू न होने के कारण रद्द कर दिया गया है। यह बीड जैसे जलसंकटग्रस्त ज़िले के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस बीच, मराठवाड़ा क्षेत्र की प्रमुख नदियों पर अब तक २६५४ कोल्हापुरी पद्धति के बांध निर्मित किए जा चुके हैं, लेकिन अधिकांश बांधों में गेट न होने के कारण वर्षा का जल बहकर व्यर्थ चला जाता है।



विशेषज्ञों के अनुसार, इन बांधों की जलधारण क्षमता लगभग २.३५ लाख घन मीटर है, लेकिन गेट की अनुपस्थिति में लगभग १४,००० हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र प्रभावित हो चुका है। यदि ये गेट लगे होते, तो कम से कम १०,००० किसानों की ज़मीन सिंचाई के दायरे में आ सकती थी। वर्तमान में ये किसान जल की कमी

के कारण मजदूरी करने को विवश हैं। हिंगोली ज़िले को छोड़कर मराठवाड़ा के २६३४ बांधों में गेट की ज़रूरत है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार कुल ७९,७८१ गेट की आवश्यकता है, जिनमें से वर्तमान में केवल ६०,२६२ गेट उपलब्ध हैं और १९,११९ गेटों की भारी कमी बनी हुई है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए

सामाजिक कार्यकर्ता और सूचना अधिकार कार्यकर्ता डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर ने उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री अजितदादा पवार से कम से कम ५२ करोड़ रुपये के बजट प्रावधान की मांग की है, जिससे गेटों की मरम्मत और स्थापना का कार्य शीघ्र पूरा किया जा सके। चोरी और लापरवाही भी बनी बड़ी बाधा

डॉ. ढवळे ने यह भी उजागर किया कि इन बांधों के गेट चोरी हो जाना भी एक बड़ी समस्या है। एक-एक गेट की लागत काफी अधिक होती है, और खेतों के खुले क्षेत्र में चोरी करना चोरों के लिए आसान होता है। परंतु, संबंधित विभाग गेट चोरी के मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने में भी लापरवाही बरतते हैं, जिससे चोरों का मनोबल

बढ़ता जा रहा है। प्रशासनिक उपेक्षा चिंता का विषय डॉ. ढवळे ने कहा कि मराठवाड़ा जैसे क्षेत्र में सिंचाई की आवश्यकता अत्यंत गंभीर है, फिर भी प्रत्येक वर्ष बजट मिलने के बावजूद कार्यों में कोई सुधार नहीं हो रहा। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और सरकार को शीघ्र ही मराठवाड़ा की ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। मराठवाड़ा में भारी निवेश

कर बनाए गए कोल्हापुरी बांध बिना गेट के निरर्थक साबित हो रहे हैं। यदि समय रहते गेट की स्थापना और मरम्मत का कार्य नहीं किया गया, तो सिंचाई की संभावना पूरी तरह समाप्त हो सकती है। यह आवश्यक है कि संबंधित अधिकारी व जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को प्राथमिकता दें और किसानों के हित में शीघ्र ठोस कदम उठाए जाएं।

रेडियो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का सबसे प्रभावशाली माध्यम-देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, २१ जून (विशेष प्रतिनिधि): रेडियो का महत्व आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। यह अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का एक शक्तिशाली और सशक्त माध्यम है - यह बात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र रेडियो महोत्सव और आशा रेडियो पुरस्कार समारोह में व्यक्त की। इस अवसर पर विभिन्न रेडियो चैनलों के छह रेडियो जॉकी - सिद्धू, अक्की, अर्चना, ब्रजेश, भूषण और सपना भट - ने मुख्यमंत्री फडणवीस का साक्षात्कार लिया। इस सत्र में उन्होंने रेडियो से जुड़ी अपनी भावनाएँ, संगीत सुनने, गीत लिखने जैसे अपने शौक और बचपन की यादें साझा कीं। मुख्यमंत्री ने एक तात्कालिक कविता भी सुनाई और गीत गाया। उन्होंने कहा, हमारे बचपन में दिन की शुरुआत रेडियो से होती थी। विविध भारती पर आने वाले गीत कभी नहीं छूटते थे। रेडियो से मेरा नाता तब से जुड़ा है। आज जब शासन स्तर पर रेडियो के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, तो मुझे अत्यंत संतोष हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि रेडियो पर जब कार्यक्रम चलता है तो भले ही व्यक्ति दिखाई नहीं देता, पर उसकी आवाज़ शब्दों के माध्यम से चित्र खींच देती है। मन की बात से संवाद का नया रास्ता मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम शुरू कर रहे दिखा दिया कि रेडियो सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि यह जनता से सीधा संवाद स्थापित करने का भी माध्यम है। रेडियो के ज़रिए संवाद की संस्कृति को नया आयाम मिला है। रेडियो नहीं होता तो मैं नहीं होती - आशा भोसले ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले ने भावनात्मक स्वर में कहा कि अगर रेडियो न होता, तो मैं भी न होती। इस अवसर पर उन्हें आशा रेडियो जीवन गौरव पुरस्कार २०२५ से सम्मानित किया गया। अन्य पुरस्कारों में शामिल रहे: आशा सर्वश्रेष्ठ पुरुष उद्घोषक पुरस्कार - जितुराज (रेडियो मिर्ची) आशा सर्वश्रेष्ठ महिला उद्घोषक पुरस्कार - मंडिशा (रेड एफएम) आशा सर्वश्रेष्ठ रेडियो केंद्र पुरस्कार - रेडियो सिटी आशा सर्वश्रेष्ठ कम्प्यूनिटी रेडियो केंद्र पुरस्कार - विकास भारती रेडियो केंद्र, नंदुरबार कार्यक्रम में कुल १२ रेडियो श्रेणियों में पुरस्कार वितरित किए गए। वर्तमान में महाराष्ट्र में १६ प्रमुख रेडियो चैनल, ५८ सामुदायिक रेडियो स्टेशन और ६० केंद्र सक्रिय रूप से कार्यरत हैं।

बीड जिले को मिला बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट: दो राष्ट्रीय महामार्ग परियोजनाओं के लिए ४२१ करोड़ रुपये मंजूर

बीड (प्रतिनिधि) - बीड जिले के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सांसद बजरंग सोनवणे के लगातार प्रयासों के बाद केंद्र सरकार ने जिले की दो प्रमुख राष्ट्रीय महामार्ग परियोजनाओं को मंजूरी देने का निर्णय लिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इन प्रस्तावों को वित्तीय वर्ष २०२५-२६ की वार्षिक योजना में शामिल करते हुए कुल ४२१ करोड़ रुपये की लागत से दो निर्माण कार्यों को हरी झंडी दी है। धारू घाट ब्लैक स्पाट पर नया चौड़ा वैकल्पिक मार्ग राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५४८ (सी) के

अंतर्गत माजलगांव से केज मार्ग पर धारू घाट का क्षेत्र अत्यंत संकरा और तीव्र चढ़ाई वाला होने के कारण यह ब्लैक स्पाट घोषित किया गया था। यहाँ लगातार दुर्घटनाएं हो रही थीं, जिससे यातायात प्रभावित होता था और जान-माल की हानि होती थी। सांसद बजरंग सोनवणे ने जुलाई २०२४ से इस घाट के स्थान पर थेटगव्हाण मार्ग से होकर नया, चौड़ा और कम चढ़ाई वाला वैकल्पिक चौपटरी मार्ग बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सड़क परिवहन मंत्रालय से लगातार अनुरोध किया था। इसका असर अब दिखा है - ११ किमी लंबे इस मार्ग के लिए १७९ करोड़



रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस परियोजना से माजलगांव, वडवणी और आसपास के तालुकों के किसानों को लाभ मिलेगा, साथ ही शेगांव से पंढरपुर तक का मार्ग सुगम और सुरक्षित बनेगा। बर्दापुर फाटा से लोखंडी सावरगाव तक

चौपटरीकरण को भी मंजूरी इसके अतिरिक्त, लातूर से लोखंडी सावरगाव मार्ग पर बर्दापुर फाटा से लोखंडी सावरगाव तक की शेष सड़क को चौपटरी बनाने की परियोजना भी मंजूर की गई है। १८ किमी की इस सड़क के लिए अनुमानित लागत २५० करोड़ रुपये रखी गई है। यह भी २०२५-२६ की वार्षिक योजना में प्रस्तावित की गई है और इसे उच्च प्राथमिकता दी गई है। सांसद सोनवणे की सक्रियता से मिल रही स्वीकृतियां सांसद बजरंग सोनवणे द्वारा जिले के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देते हुए कई

परियोजनाओं को गति देने का प्रयास किया गया है। धारू घाट के वैकल्पिक मार्ग के माध्यम से न सिर्फ दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सकेगी, बल्कि लोगों के जीवन भी सुरक्षित होंगे। इस क्षेत्र में पूर्व में कई हादसों के कारण अनेक परिवार उजड़ चुके हैं। अन्य प्रस्ताव भी स्वीकृति के मार्ग पर इसके अतिरिक्त, अहमदपुर से पिंपळा धायगुडा, धायगुडा से लोखंडी सावरगाव, और लोखंडी सावरगाव से मांजसुंवा तक के मार्गों के चौपटरीकरण के प्रस्ताव भी समितियों के पास भेजे गए हैं और उन्हें भी शीघ्र ही मंजूरी मिलने की संभावना है।

स्थानीय स्वराज संस्थाओं में 'माझी वसुंधरा अभियान ६.०' होगा लागू-पंकजा मुंडे

- रिपोर्ट: जमीर काज़ी, मुंबई, २१ जून पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और जागरूकता के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा 'माझी वसुंधरा' नामक अभिनव अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अगले चरण माझी वसुंधरा अभियान ६.० को आगामी वर्ष १ अप्रैल २०२५ से ३१ मार्च २०२६ तक राज्य की सभी स्थानीय स्वराज संस्थाओं में लागू किया जाएगा। यह जानकारी पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे ने शनिवार को दी। पंचतत्त्वों के संरक्षण पर केंद्रित रहेगा अभियान पंकजा मुंडे ने बताया कि यह अभियान प्रकृति के पाँच मूलभूत तत्व - पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश - पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्याओं के प्रति नागरिकों में

जागरूकता बढ़ाना है। अभियान के अंतर्गत विभिन्न शासकीय योजनाओं, कार्यक्रमों और उपायों को एकत्रित कर मिशन मोड में स्थानीय स्वराज संस्थाओं के माध्यम से लागू किया जाएगा। इसके लिए अभियान मार्गदर्शन प्रारूप संच (टूलकिट) तैयार किया गया है, जो अब तक पांच चरणों में लागू हो चुका है। कार्यों का मूल्यांकन और पुरस्कार अमृत गट की संस्थाओं के लिए: १५,१२५ अंक अमृत गट को छोड़कर अन्य नगरीय संस्थाओं के लिए: १४,६२५ अंक स्थानीय संस्थाओं के कार्यों का मूल्यांकन स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा किया जाएगा, और ५ जून २०२६ को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर परिणाम घोषित कर उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा।



ताइवान में आयोजित 'ग्लोबल समर स्कूल' के लिए शहबाज़ मनयार का चयन

अंबाजोगाई, २१ जून:(संवाददाता) ताइवान की नेशनल चुंग हसिंग यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स द्वारा २४ जून से ४ जुलाई २०२५ तक 'ग्लोबल समर स्कूल' का आयोजन किया जा रहा है। इस अंतरराष्ट्रीय समर स्कूल में भाग लेने वाली मुंबई विश्वविद्यालय की १४ सदस्यीय टीम में अंबाजोगाई के शहबाज़ म. फारूक मनयार का चयन किया गया है। चयनित दो वरिष्ठ शोधार्थियों में शहबाज़ मनयार भी शामिल हैं। 'ग्लोबल समर स्कूल' का विषय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (-ख), जैव प्रौद्योगिकी, सतत शासन प्रणाली और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (डज्जि) पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम में विषय आधारित व्याख्यान, देशों द्वारा डज्जि की प्रगति पर प्रस्तुतियाँ, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, वाद-विवाद, भविष्य में सहयोग की संभावनाएँ और फील्ड विज़िट्स शामिल रहेंगी। यह समर स्कूल शोधार्थियों और विद्यार्थियों

को वैश्विक स्तर का अनुभव प्रदान करेगा। शोधार्थी इस समर स्कूल में समूह चर्चा के माध्यम से लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और नीतिगत सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। इस अवसर पर महाराष्ट्र की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री आदिती तटकरे ने मुंबई विश्वविद्यालय की टीम से भेंट कर तैयारी की समीक्षा की और उन्हें शुभकामनाएँ दीं। शहबाज़ मनयार इस समर स्कूल में सतत विकास लक्ष्य क्रमांक ४ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उससे संबंधित १० उपलक्ष्यों को २०३० तक प्राप्त करने हेतु भारत की प्रगति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इस विषय पर उन्हें प्रोफेसर मृदुल निले का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। शहबाज़ मनयार वर्तमान में मुंबई विश्वविद्यालय के नागरिकशास्त्र और राजनीतिशास्त्र विभाग में वरिष्ठ शोधार्थी के

रूप में कार्यरत हैं और निर्वाचन राजनीति पर पीएच.डी. कर रहे हैं। उन्होंने पहले ही ड्राइव, छह और गठक जैसे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएँ उत्तीर्ण की हैं। इसके अतिरिक्त, वह छत्तीसगढ़ राज्य का एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनकर अंबाजोगाई और बीड ज़िले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर चुके हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि और मराठी माध्यम से शिक्षा प्राप्त यह युवक आज अपनी मेहनत और प्रतिभा के बलबूते अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि ग्रामीण भारत का युवा भी वैश्विक स्तर पर देश की शान बन सकता है। शिक्षा नगरी माने जाने वाले अंबाजोगाई के लिए यह गर्व की बात है। इस उपलब्धि पर शहबाज़ मनयार को हर स्तर से बधाईयाँ मिल रही हैं।



उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

तनावमुक्त जीवन के लिए योग अनिवार्य-जिलाधिकारी विवेक जॉनसन

बीड, २१ जून (संवाददाता): व्यस्त और भागदौड़ भरी जीवनशैली में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए प्रतिदिन योगाभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। उक्त विचार जिलाधिकारी विवेक जॉनसन ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर व्यक्त किए।

उन्होंने कहा कि योग एक पारंपरिक भारतीय पद्धति है, जिसकी परंपरा पिछले पाँच हजार वर्षों से चली आ रही है। पूर्वजों ने भी योग, ध्यान और साधना के माध्यम से स्वयं को स्वस्थ और तनावमुक्त बनाए रखा। आज के युग में विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने और एकाग्रता बढ़ाने के लिए ध्यान साधना आवश्यक हो गई है।



है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को योग अवश्य करना चाहिए और शारीरिक व मानसिक विकास हेतु स्कूल व कॉलेजों के छात्रों को भी योग से जुड़ना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान योग दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खिलाड़ी राधा वझे, सुभाषिनी वझे, शिवाजी घोडके और राधा तांबे का जिलाधिकारी विवेक जॉनसन के

हाथों पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया गया। योगगुरु विनायक वझे, विकास गवते और राधा तांबे ने उपस्थित जनों को योग अभ्यास करवाया। पूर्ववेद स्पोर्ट्स अंड हेल्थ प्रमोशन अक्वैडमी, बीड के योग खिलाड़ियों और शिवाजी घोडके, राधा तांबे ने योग का प्रदर्शन भी किया।

इस कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके, निवासी उप जिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी, जिला क्रीड़ा अधिकारी अरविंद विद्यागर, तहसीलदार चंद्रकांत शेळके, जिला नियोजन अधिकारी सुधाकर चिंचाणे, जिला कोषागार अधिकारी लहु गळगुंडे, जिला शल्य चिकित्सक संजय राऊत, जिला आरोप्य अधिकारी डॉ. उल्हास गंडाळ, माध्यमिक शिक्षा अधिकारी संजय पंचगळे, प्राथमिक शिक्षा अधिकारी प्रियाराणी पाटील, भगवान फुलारी, जिला आयुष अधिकारी आनंद कुलकर्णी, पुरुषोत्तम पिंगळे, कार्यकारी अभियंता रविंद्र तोडे, वरिष्ठ क्रीड़ा संघटक प्रा. जे.पी. शेळके, उपशिक्षणाधिकारी नानाभाऊ हजारे, भगवान सोनवणे, रंगनाथ राऊत, अशोक कदम सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी, नागरिक, खिलाड़ी, पत्रकार और व्यापारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

कार्यक्रम के सफल आयोजन में जिला क्रीड़ा अधिकारी अरविंद विद्यागर के मार्गदर्शन में क्रीड़ा अधिकारी अनिकेत काळे, कालिदास होस्कर, क्रीड़ा मार्गदर्शक सतिष राठोड, अविनाश पाटील, रेवनाथ शेलार, जितेंद्र आराक, धनेश करांडे, प्रीति काळे, मंगेश वडमारे और गणेश वीर ने विशेष योगदान दिया।

'डीबीटी' प्रणाली से संजय गांधी निराधार योजना खुद हो गई निराधार

हजारों लाभार्थी ४-५ माह से वंचित, लोकप्रतिनिधियों से तत्पर हस्तक्षेप की मांग-जे.डी. शाह



बीड, २१ जून: बीड ज़िले के हजारों वृद्ध, निराधार और ज़रूरतमंद नागरिकों के लिए आशा की किरण कही जाने वाली संजय गांधी निराधार योजना आज खुद संकट में फँसी हुई है। इसी तरह श्रावणबाल निवृत्ति वेतन योजना और इंदिरा गांधी वृद्धापकाल योजना भी तकनीकी कारणों से लाभार्थियों को राहत देने में विफल साबित हो रही है। इन तीनों योजनाओं के हज़ारों लाभार्थियों को पिछले चार से पाँच महीनों से एक भी पैसा नहीं मिला है, जिससे वृद्ध, दिव्यांग और विधवा महिलाओं में भारी असंतोष और निराशा का वातावरण है।

वरिष्ठ समाजसेवक जे.डी. शाह ने

अंतर्गत चलने वाली इन योजनाओं का पैसा डीबीटी (डायरेक्ट बेंचिफिट ट्रांसफर) के जरिए भेजा जाता है। लेकिन आधार लिंक न होना, मोबाइल नंबर अपडेट न होना, या बैंक खातों की जानकारी अधूरी रहना – ऐसी तकनीकी परेशानियाँ सरकार की मंशा के विरुद्ध एक बड़ी दीवार बन गई हैं। कई लाभार्थियों को इस कारण महीनों से कोई सहायता नहीं मिली है।

बुजुर्गों और दिव्यांगों को हो रही भारी परेशानी तहसील कार्यालयों के बाहर प्रतिदिन बड़ी संख्या में वृद्ध, अपंग और निराश्रित महिलाएँ सहायता की उम्मीद में घंटों खड़ी रहती हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं मिलता। बीमार लोगों को दवा खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। सरकार ने पारदर्शिता के नाम पर डीबीटी लागू तो किया, लेकिन ज़मीनी स्तर पर प्रशासन की लापरवाही और तकनीकी अक्षमता के कारण यह योजना लोगों के लिए निराशा का कारण बनती जा रही है।

कर्मचारियों का असंवेदनशील

व्यवहार भी चिंता का विषय जे.डी. शाह ने यह भी कहा कि शासन ने स्पष्ट आदेश दिए थे कि तहसील कार्यालय के बजाय गाँव-गाँव जाकर डीबीटी प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि वृद्ध और दिव्यांगों को कार्यालय आने की ज़रूरत न हो। लेकिन अधिकारी और कर्मचारी इन आदेशों को नजरअंदाज़ कर रहे हैं और वृद्धजन तहसीलों में भटकने को मजबूर हैं। आवश्यक है तत्काल समाधान

प्रेस पत्र के अंत में जे.डी. शाह ने मांग की कि ज़िला प्रशासन और लोकप्रतिनिधि इस गंभीर स्थिति को नजरअंदाज़ न करें और तत्परता से तकनीकी समस्याओं को दूर कर लाभार्थियों के खातों में लंबित राशि तत्काल जमा करें, ताकि इन योजनाओं का उद्देश्य सार्थक हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यही स्थिति रही, तो संजय गांधी निराधार योजना सचमुच निराश्रितों के लिए निराशा की योजना बन जाएगी।

करें और तत्परता से तकनीकी समस्याओं को दूर कर लाभार्थियों के खातों में लंबित राशि तत्काल जमा करें, ताकि इन योजनाओं का उद्देश्य सार्थक हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यही स्थिति रही, तो संजय गांधी निराधार योजना सचमुच निराश्रितों के लिए निराशा की योजना बन जाएगी।

देवेंद्रजी कसरत नहीं करते, लेकिन ध्यान अवश्य करते हैं-अमृता फडणवीस

रिपोर्ट : रामिज़ काज़ी, मुंबई, २१ जून

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने योग के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, देवेंद्रजी एक योगी हैं। वे कसरत तो नहीं करते, लेकिन नियमित रूप से ध्यान करते हैं।

अमृता फडणवीस मुंबई में एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा आयोजित योग शिविर में बृहन्मुंबई महानगरपालिका के

इस अवसर पर उन्होंने कहा, आज हमने वारकरी साथियों के साथ योगासन किए। पुणे के कॉलेज भी इस आयोजन में शामिल हुए, जिससे यह आयोजन और भव्य बन गया।

हमारी प्राचीन जीवनशैली और चिकित्सा पद्धति सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि मन को भी स्वस्थ रखने की परंपरा रखती है – यही योग की ताकत है। मोदीजी के प्रयासों से योग को अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्थान मिला है। राज्य में शांति प्रिय



अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ योग अभ्यास कर रही थीं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि योगासनों की नियमितता मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों में जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी है। पुणे में मुख्यमंत्री ने वारकरी श्रद्धालुओं के साथ किया योग

इधर पुणे में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य सरकार के सौजन्य से आयोजित वारकरी भक्तियोग उपक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हज़ारों वारकरी श्रद्धालुओं, विद्यार्थियों और पुणे के नागरिकों के साथ योगाभ्यास किया।

सरकार है, विवादास्पद भाषा ठीक नहीं शिवसेना के स्थापना दिवस पर उद्भव ठाकरे द्वारा दिए गए विवादित बयान कम ऑन किल मी पर प्रतिक्रिया देते हुए अमृता फडणवीस ने कहा, आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है, हमें शांत और प्रसन्नचित रहना चाहिए। हमारा देश शांति प्रिय है और राज्य में भी शांति प्रिय पार्टी सत्ता में है। ऐसे में किसी को भी आक्रामक और विवादास्पद भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

उनकी यह टिप्पणी उद्भव ठाकरे पर एक सीधा राजनीतिक कटाक्ष मानी जा रही है।

इकरा शाहीन उर्दू हाई स्कूल में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया



जलगांव (अकील खान ब्यावली): इकरा एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित इकरा शाहीन उर्दू हाई स्कूल, महेरुन, जलगांव में २१ जून २०२५ को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह कार्यक्रम प्रातःकालीन सभा के दौरान संपन्न हुआ, जिसमें विद्यार्थियों ने पूरे जोश और सहभागिता के साथ भाग लिया।

इस अवसर पर सुपरवाइजर जाकिर बशीर शेख और बरकत शेख ने छात्रों को योग के विभिन्न प्रकारों और महत्वपूर्ण आसनों की जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि नियमित योगाभ्यास कैसे न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि मानसिक एकाग्रता और आंतरिक शांति प्रदान करता है।

कार्यक्रम की सראहना सोसाइटी के अध्यक्ष अब्दुलकरीम सालार, अन्य डायरेक्टर्स और विद्यालय के प्राचार्य काज़ी ज़मीरुद्दीन ने की। उन्होंने इस प्रेरणादायक आयोजन को सफल बनाने के लिए स्टाफ सदस्यों और विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई दी।

ईरान ने इज़राइल के वाइजमैन साइंस इंस्टीट्यूट को नष्ट कर, परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याओं का बदला लिया

तेहरान

ईरान ने इज़राइल में स्थित प्रतिष्ठित वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (Weizmann Institute) पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर उस पर हमला कर बदला लिया – इस संस्थान में इजरायली वैज्ञानिकों की हत्या का बदला लेने के उद्देश्य से की गई प्रतिक्रिया देखी जा रही है ।

मिसाइल हमलों में संस्थान के दो भवनों को भारी क्षति पहुंची, जिनमें एक जीवन-विज्ञान प्रयोगशाला थी और दूसरा केमिस्ट्री के लिए निर्माणाधीन भवन था। इसके अलावा दर्जनों अन्य भवनों को भी क्षतिग्रस्त किया गया ।

किसी भी कर्मचारी या वैज्ञानिक की मौत की सूचना नहीं है, लेकिन इस हमले से वर्षों



के वैज्ञानिक अनुसंधान नष्ट हो गए – जिनमें हृदय संबंधी जैविक प्रयोग, आनुवंशिक शोध, DNA/RNA अनुक्रमण संबंधी डेटा शामिल हैं । वाइजमैन इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर ओरेन शुल्डिनर ने कहा, यह ईरान के लिए 'नैतिक विजय' है – उन्होंने आविष्कार और अनुसंधान के 'राजसी गहने' को क्षतिग्रस्त किया । संस्थान पर हुए हमले के कारणों पर

विशेषज्ञों का कहना है कि यह इज़राइल द्वारा ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों और सैन्य अधिकारियों की लक्षित हत्याओं का बदला है, जिससे यह स्पष्ट संदेश जाता है: विज्ञान का क्षेत्र अब युद्धभूमि में तब्दील हो गया है। एक अनुमान के अनुसार, खाली प्रयोगशाला बनाकर बस उपकरणों से लैस करने में करीब ४००-८०० करोड़ (५०-१०० मिलियन डॉलर) का खर्च आएगा। ईरान का यह कदम इज़राइल-विरोधी अभियान का हिस्सा माना जा रहा है और यह संघर्ष अब पारंपरिक सैन्य लक्ष्यों से आगे बढ़कर वैज्ञानिक अवसंरचनाओं को निशाना बना रहा है। वाइजमैन इंस्टीट्यूट पर यह हमला तनावपूर्ण क्षेत्रीय माहौल में नाटकीय रूप से सैन्य तथा वैज्ञानिक रणनीतियों की जटिलता को उजागर करता है।

तुर्की में OIC विदेश मंत्रियों की बैठक जारी, इरान और गाज़ा संकट पर विशेष ध्यान

इस्तांबुल एजेंसी

तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के ५१वें विदेश मंत्रियों की बैठक में प्रमुख एजेंडा में प्रमुख रूप से इज़राइल-इरान संघर्ष और गाज़ा संकट शामिल हैं ।

चर्चा का आरंभ टर्किश विदेश मंत्री हाकन फिदान ने किया, जिन्होंने इसे क्षेत्र में एक इज़राइल समस्या कहा और पास पड़ोसी इरान पर इज़राइल के हालिया हमलों की कड़ी निंदा की ।

जखउ के उद्घाटन भाषण में राष्ट्रपति रजब तैय्यब एर्दोगान ने इज़राइल पर कठोर आरोप लगाते हुए कहा कि यह गैरकानूनी और खतनाक हमलों के जरिए एक नए युद्ध की तैयारी कर रहा है, और उन्होंने क्षेत्र में अफगानी नीति लागू करने की आवश्यकता जताई ।

इरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची भी बैठक में उपस्थित हैं और उन्होंने कहा कि तेहरान अपना रक्षा पक्ष स्पष्ट रूप से उजागर करने के लिए तैयार है, साथ ही बैठक में उनका

प्रस्ताव विशेष सत्र बुलाने का था ताकि इज़राइल-इरान संघर्ष पर बेहतर विचार-विमर्श हो सके ।

अपराह्न में एक बंद सत्र का आयोजन हुआ, जिसमें सभी जखउ सदस्य विशिष्ट रूप से शामिल हुए, और इस सत्र का केंद्र इज़राइल पर हमलों और उसका असर था ।

बैठक में ३७ से अधिक विदेश मंत्री उपस्थित हैं, जिसमें यूरोपीय, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई व्यापक सहभागिता दृष्टिगत है; कुल मिलाकर लगभग १,००० प्रतिनिधियों

की भागीदारी देखी जा रही है ।

एर्दोगान ने साथ ही कहा कि जखउ, एक रूपांतरित विश्व में मानवाधिकारों और न्याय की मजबूत आवाज़ बनकर कार्य करे, और द्वारा समाधान को प्राथमिकता दें ।

इस बैठक का उद्देश्य न केवल हाल की हिंसक घटनाओं की कड़ी निंदा करना और तत्काल संघर्ष विराम की मांग करना है, बल्कि विश्व स्तर पर मुस्लिम देशों की एकजुट प्रतिक्रिया और कूटनीतिक प्रयासों को मजबूत बनाना भी शामिल है।